बरुण मित्रा भा.प्र.से.
Barun Mitra, IAS

सचिव
न्याय विभाग
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार
SECRETARY
DEPARTMENT OF JUSTICE
MINISTRY OF LAW & JUSTICE
GOVERNMENT OF INDIA

अर्ध सरकारी पत्रांक-15011/35/2021-न्याय (एयू) दिनांकः 12 फरवरी, 2021

मैं आपको न्याय विभाग से संबंधित जनवरी, 2021 माह के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के बारे में अवगत कराना चाहूंगा।

1. **उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्तिः**
   गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति दिनांक 07-01-2021 की अधिसूचना के तहत की गई थी।

2. **मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद से त्यागपत्रः**
   मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति श्री सुनील कुमार अवस्थी ने दिनांक 02-01-2021 से त्यागपत्र दिया। इसे दिनांक 29-01-2021 को अधिसूचित किया गया।

3. **बुनियादी ढांचा विकास के लिए केंद्र प्रायोजित स्कीमः**
   इस माह के दौरान न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास हेतु केंद्र प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 253.12 करोड रुपए की राशि जारी की गई है।

4. **फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्टः**
   फास्ट ट्रेक स्पेशल कोर्ट स्थापित करने की योजना के सशक्त कार्यान्वयन के उद्देश्य से विशिष्ट पोक्सो न्यायालय सहित शेष फास्ट ट्रेक कोर्ट खोलने के मामले में गति लाने; जनशक्ति के नियोजन; फास्ट ट्रैकिंग केस निपटान; जारी निधि के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने और सफलता के वृतांत को साझा करने के लिए 19-20 जनवरी, 2021 को उच्च न्यायालय के सभी

रजिस्ट्रार जनरलों और सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विधि सचिवों की एक वर्चुअल बैठक आयोजित की गई थी।

5. **ईकोर्ट मिशन मोड परियोजना का फेज-।।:**

विगत 6 माह के दौरान,भारत के उच्चतम न्यायालय की ई समिति ने ईकोर्ट परियोजना के अंतर्गत दी गई आईसीटी सेवाओं के संबंध में 19 प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जिनमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, जिला न्यायपालिका के न्यायाधीशों, न्यायालय स्टाफ, अधिवक्ताओं और मास्टर प्रशिक्षकों सहित लगभग 1.6 7 लाख व्यक्तियों को शामिल किया गया। दिसंबर, 2020 की समाप्ति तक, जिला न्यायालयों ने 45.73 लाख मामलों की सुनवाई की जबकि उच्च न्यायालय द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर 20.60 लाख मामलों की सुनवाई की। भारत के उच्चतम न्यायालय दिनांक 31-01-2021 तक 52353 मामलों की सुनवाई करके वर्चुअल सुनवाई के मामले में वैश्विक स्तर पर नंबर एक पर रहा।

दिनांक 20-01-2021 तक, यातायात अपराधों के मामलों का निपटारा करने के लिए 7 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में नौ वर्चुअल न्यायालय स्थापित किए गए हैं। इन न्यायालयों में 41,98,095 मामलों की सुनवाई की गई और 139.25 करोड रुपए के जुर्माने की वसूली की गई। दिल्ली उच्च न्यायालय ने परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत चेक बाउंस के मामलों की सुनवाई के लिए हाल ही में 34 डिजिटल न्यायालय शुरू किए हैं।

6. **ईज ऑफ डूइंग बिजनेस:**

ईज आफ डूइंग बिजनेस का प्रभावकीय परिवेश सृजित करने के संबंध में नियमित अनुवर्ती कार्रवाई के परिणाम स्वरूप, बंबई उच्च न्यायालय ने 100 करोड़ रुपए से अधिक के उच्च मूल्य वाणिज्यिक विवादों/मामलों के निपटारे के लिए मुंबई में एक समर्पित न्यायालय स्थापित किया है। पटना उच्च न्यायालय ने भी उच्च मूल्य के अर्थात 500 करोड़ रुपए से अधिक के वाणिज्यिक विवादों के समाधान के लिए एक वाणिज्यिक अपील प्रभाग और दो विशेष वाणिज्यिक पीठों का गठन किया है।

कोलकाता में समर्पित वाणिज्यिक न्यायालयों के कार्य संचालन के संबंध में दिनांक 11-01- 2021 को एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी जिसमें नोडल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति श्री राजेश बिंदल और सचिव (न्याय) राज्य सरकार के पदाधिकारियों के साथ उपस्थित थे।

7. **टेली लॉ:**

55148 व्यक्तियों को कानूनी सलाह दी गई थी जिसमें (14906) महिलाएं, (15621) अनुसूचित जाति, (11385) अनुसूचित जनजाति और (17367) अन्य पिछड़े वर्ग के लाभार्थी शामिल थे। 31 जनवरी, 2021 तक दी गई सलाह का कुल आंकड़ा 5,81,280 पहुंच गया है। 19 राज्यों में 31 प्रशिक्षण और जागरूकता सत्र संचालित किए गए थे जिनमें 637 वी एल ई और 523 पीएलबी ने भाग लिया

8. न्याय बंधु (प्रो बोनो कानूनी सेवाएं):

न्याय बंधु मोबाइल एप्लीकेशन पर 78 नए वकीलों ने पंजीकरण किया। अब तक, इस कार्यक्रम के तहत कुल 2370 वकील पंजीकृत हो चुके हैं। न्याय बंधु पैनल कार्यक्रम के तहत इलाहाबाद, झारखंड, पटना और उत्तराखंड उच्च न्यायालयों द्वारा 67 प्रो बोनो वकीलों का नामांकन किया गया था। 44 विधि विद्यालयों के छात्रों को 11 विधि विश्वविद्यालयों/विद्यालयों द्वारा प्रो बोनो गतिविधियों के लिए पंजीकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त, महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय मुंबई और हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय शिमला, हिमाचल प्रदेश प्रो बोनो क्लब स्कीम से जुड़ चुके हैं। नि:शुल्क वकालत की संस्कृति तेजी से पैर पसार रही है।

9. उत्तर पूर्व और जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के संघ राज्य क्षेत्रों में न्याय तक पहुंच:

- जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के विधिक सेवा प्राधिकरण ने 50 कानूनी सहायता क्लीनिकों के माध्यम से 120 विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। 7320 प्रतिभागियों (4422 पुरुष और 2896 महिला) को 15 चयनित कानूनों के बारे में बताया गया। माह के दौरान, व्यक्तियों की शिकायतों की पहचान करने के लिए 130 घर-घर सर्वेक्षण किए गए और इसके माध्यम से 1044 व्यक्तियों (130 अनुसूचित जाति, 161 अनुसूचित जनजाति और 754 सामान्य) तक पहुंचा गया।

- राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, अरुणाचल प्रदेश ने 57 ग्राम प्रमुखों के लिए एक दिवसीय कानूनी पुनश्चर्या प्रशिक्षण आयोजित किया। माह के दौरान, 10 कानूनी सहायता क्लीनिकों के माध्यम से 66 व्यक्तियों तक कानूनी सुविधा प्रदान की गई।

10. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा):

- मणिपुर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने मणिपुर के 15 अधिवक्ताओं के लिए मध्यस्थता पर मेडिएशन एंड कॉन्सिलिएशन प्रोजेक्ट कमिटी, भारत के उच्चतम न्यायालय के सहयोग से मणिपुर का पहला 40 घंटे का ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।

- आंध्र प्रदेश और गोवा राज्य में ई लोक अदालतें संचालित की गई जिनमें 3683 मामलों का निपटान किया गया।

11. ए सी सी के निर्देशों का अननुपालनः

शून्य

भवदीय,

हस्ताक्षर /-

(बरुण मित्रा)

श्री राजीव गौबा
मंत्रिमंडल सचिव,
मंत्रिमंडल सचिवालय,
राष्ट्रपति भवन,
नई दिल्ली

प्रति:

माननीय विधि एवं न्याय मंत्री के निजी सचिव, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, शास्त्री भवन, नई दिल्ली ।

(बरुण मित्रा)